भारत चीन से कितना आगे है

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(10 नवंबर, 2017)

कौशिक बसु (कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्व बैंक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

भारत का धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक स्पष्टता, भाषण की स्वतंत्रता में प्रारंभिक निवेश, जिसने शुरुआती वर्षों में आर्थिक विकास को मुश्किल बना दिया, जो अब भुगतान करने की स्थिति में आ चुका है, लेकिन सभी भविष्यवाणियां आशंका और चेतावनियों के साथ संबद्ध हैं।

यह पिछले महीने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की वजह से है, जहाँ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर चीन के विकास की संभावनाओं पर हाल के सप्ताहों में हुई सम्मेलनों, बैठकों और चर्चाओं में जो तेजी आई है।

डोनाल्ड ट्रम्प के निराशाजनक प्रदर्शन और शी जिनपिंग के उल्लेखनीय नेतृत्व के परिणामस्वरूप, दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक राजनीतिक प्रभाव को प्रतिद्वंद्वी करने की शुरुआत की है। लेकिन, जीएनपी या प्रति व्यक्ति आय से मापा गया अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, चीन को अब भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

चीन का आर्थिक प्रदर्शन अब 1978 के बाद से बहुत अच्छा रहा है, जहाँ ज्यादातर विश्लेषकों की यही प्रवृत्ति रही है कि वे इसे और बढ़ा कर दिखाए और संभावनाओं के संदर्भ में चीन को भारत के आगे दिखाये। फिर भी, लंबे समय से चलने वाली आर्थिक संभावनाओं के संदर्भ में, लेखक के अनुसार भारत को चीन से आगे स्थान देने के कई कारण है। चूंकि यह एक विरोधाभासी दृश्य है, इसलिए इसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

1969 से चीन का आर्थिक प्रदर्शन, एक वर्ष जिसमें इसकी विकास दर अविश्वसनीय 16.9 प्रतिशत थी और 1978 से और अधिक निरंतर रहा था। सफलता का एक कारण इसके नेताओं के लिए मजबूत शक्ति है। इससे चीन को कठिन सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद मिली। भारत के कर्कश लोकतंत्र ने नेताओं पर और अधिक मजबूती रखी और अक्सर उन्हें आवश्यक सुधार करने के लिए कमजोर बना दिया।

इसके विपरीत, भारत का धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक खुलापन, भाषण की स्वतंत्रता में शुरुआती निवेश, जो शुरुआती वर्षों में आर्थिक विकास के लिए मुश्किल बना था, अब भुगतान करने की स्थिति में है।

नवउदार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार, चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास इसके विकास के ठोस सबूत मौजूद है, इसलिए बहस का निपटारा यह हुआ कि नवउदार अर्थशास्त्र गलत है। हालांकि, चीन के असाधारण प्रदर्शन के बारे में कई चिंताजनक सवाल मौजूद हैं। इसकी जीडीपी का असंगत राशि राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र द्वारा निर्मित है और कम्युनिस्ट पार्टी के पास निजी कंपनियों के बोर्डों पर प्रतिनिधि हैं। यह एक शीर्ष-डाउन प्रणाली है जो ज्यादातर देशों में असफल रही है, लेकिन चीन में सफल रहा है।

चीन के अनुभव से पता चलता है कि बुद्धिमान नेताओं द्वारा संचालित एक दंडकारी प्रणाली, लाभांश प्राप्त कर सकती है। माओ जेडोंग ने बड़ी गलतियां कीं, लेकिन यह उनके नेतृत्व में था कि देश ने स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश किया, जिसने चीन को एक असाधारण प्रतिभाशाली कर्मचारियों की संख्या दी है। देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में, बाजार की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया था और साथ ही, विनिमय दर के लिए एक चतुर हस्तक्षेप नीति तैयार की गई थी, जिसने निर्यात को बढ़ावा दिया था। और शी जिनपिंग में हम प्रबंधन और नियंत्रण और साथ ही वैश्विक संबंध के लिए एक असाधारण क्षमता देखते हैं।

तो फिर, सवाल यह उठता है कि हमे चीन के बारे में चिंता क्यों है? केवल एक जोरदार, टॉप-डाउन प्रणाली के कारण, कुछ समय बाद, अपना स्वयं का उद्देश्य प्राप्त करता है और जब ऐसा होता है, तो राष्ट्र के हितों के खिलाफ शीर्ष क्रम में उन लोगों के हितों के विपरीत हो जाता है। विकास को बढ़ावा देने के बजाय राजनैतिक शक्ति को संरक्षित करने के लिए मजबूरकारी संरचना का उपयोग किया जाता है।

मुख्य सबक यह है कि एक टॉप-डाउन दंडकारी सिस्टम थोड़ी देर के लिए काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक चलने में उलटा पड़ जाता है। एक आकर्षक बातचीत में, ब्रिटिश संगीतकार चार्ल्स हाजलवुड ने बताया कि कैसे संगीतकार के बलप्रयोग और तानाशाही अच्छे संगीत का उत्पादन कर सकते हैं; लेकिन वास्तव में महान

संगीत व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संगीतकार और ऑर्केस्ट्रा के बीच विश्वास की आवश्यकता को दर्शाता है। यह न केवल आर्केस्ट्रा के लिए बल्कि निगमों और सरकारों के लिए उतना ही सच है।

चीन और भारत जैसे समाज में, एक विशेष समस्या भ्रष्टाचार के नियंत्रण से संबंधित है। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना व्यापक है, नेता भले ही वे इसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी उत्सुक हों, एक विकल्प का सामना करना पड़ता है कि वे दोस्तों या विपक्ष में से किसका चुनाव करेंगे। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो स्व-संरक्षण की प्रवृत्ति से उपजी है, बाद के बाद जाना है। जल्द ही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, चुप्पी असंतोष का एक साधन बन जाता है। भारत और चीन दोनों ही इस जोखिम का सामना करते हैं, लेकिन फ्री मीडिया की अनुपस्थिति के कारण यह चीन के लिए बड़ा जोखिम हो जाता है।

चीनी शीर्ष-डाउन प्रणाली सर्वव्यापी है कि इसे नष्ट करना असंभव हो सकता है। इतिहास के माध्यम से इतने सारे देशों की तरह जब ऐसी व्यवस्था में कुछ खराबी हो, तो राजनैतिक शक्ति संरक्षण पर अर्थव्यवस्था का झुकाव कम हो जाता है। और इसमें भारत की ताकत निहित है। हमे लोकतंत्र, खुलेपन और फ्री मीडिया के प्रति राष्ट्र की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहिए, यह अब लाभ देने की स्थिति में आ चुका है। वर्ष 2005 से भारत के उच्च विकास में कई सहायक रहे हैं, लेकिन शुरुआती (और निस्संदेह महंगा) सामाजिक और राजनीतिक निवेश उनके बीच प्रमुख हैं। इस कारण से लेखक का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देगा। इसकी प्रणाली निरंतर असहमति के लिए खुले छिद्र के कारण विकास को जरूर कर सकता है, लेकिन विकास होगा, ये निश्चित है।

डेमोक्रेटिक राष्ट्र, निश्चित रूप से गलत मोड़ ले सकते हैं। हमने मैककार्थी वर्षों के दौरान 1950 के दशक के प्रारंभ में संयुक्त राज्य में यह देखा है और भारत में, 1975-77 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था। लेकिन स्वतंत्रता की परंपराओं और विशेष रूप से गुमनाम मतपत्र, इन्हें समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि अमेरिका और भारत में हुआ था। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मेरे (लेखक) आशावाद का कारण है।

सभी पूर्वानुमान, हालांकि चेतावनियों के साथ आते हैं; चीजें गलत हो सकती हैं। मैं (लेखक) गलत नीति के हस्तक्षेप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वह पिछले नवंबर की दुर्भावनापूर्ण विमुद्रीकरण या जीएसटी की खराब डिजाइन हो। हाल के वर्षों में भारत के लिए बड़ा खतरा धार्मिक जागरूकता का उदय है। इन कृत्यों का नेतृत्व लोग अपने ही राष्ट्र के बारे में हीनता के गहरे भाव के साथ घिर गये हैं और इसलिए वे पांच सौ साल पहले उनकी महानता के बारे में चिल्लाते हैं और अन्य समाज के कट्टरपंथी और प्रमुख समाज के अनुयायियों की नकल करते हैं। असंतोष और फ्री मीडिया की चुप्पी और इस समूह से खतरे और यहां तक कि वास्तविक हिंसा का इस्तेमाल भी भारत के लिए एक वास्तविक जोखिम है। एक छोटी सी संभावना यह है कि यह समूह अपनी असुरक्षा और अन्य के वायरल नफरत से भारत को स्थिर बनाएगा। लेकिन मैं (लेखक) आशावादी रहता हूं और विश्वास करता हूं कि यह सिर्फ एक पहला चरण है।

संबंधित तथ्य

चीन की सामरिक मजबूरी

- मौजूदा समय में चीन दक्षिण चीन सागर समेत कई मोर्चों पर घिरा हुआ है।
- ताइवान और तिब्बत मुद्दे पर चीन को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है।
- झिंगझियांग प्रांत में चीन अलगाववादियों का सामना करना पड़ रहा है।
- चीन की वन बेल्ट, वन रोड की योजना पर असर पड़ सकता है।
- दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा।

भारत के लिए चिंता की वजह

- पाक सीमा पर लगातार तनाव की वजह से चीन के साथ संघर्ष करना आसान नहीं।
- एनएसजी की सदस्यता हासिल करने के लिए चीन का समर्थन जरूरी।
- चीन के मुकाबले सैन्य क्षमता में कमी।

चीन के लिए अहम भारतीय बाजार

- 2010 के दौरान भारत में चीन की 30-40 फर्में काम कर रही थीं। लेकिन 2017 के आते-आते ये संख्या करीब 500 हो चुकी है।
- 1.6 अरब डॉलर करीब 104 अरब रुपये का निवेश पिछले 16 वर्षों में चीन का भारत में हुआ है।
- 2015 में दोनों देशों के बीच करीब 70 अरब डॉलर यानि 4550 अरब रुपये का कारोबार हुआ है।
- जनवरी से सितंबर 2016 के बीच करीब 351 अरब रुपये का सामान चीन से भारत आयात हुआ।
- 2020 तक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार करीब 26,598 अरब रुपये पहुंचने का अनुमान है।

(ये सभी आंकड़े भारत सरकार और चीन की सरकारी मीडिया के रिपोर्ट पर आधारित है।)

संभावित प्रश्न

चीन विश्व में मुक्त व्यापार एवं खुले बाजार के प्रमुख के रूप में अमेरिका की पारम्परिक रूप से विद्यमान भूमिका में स्वयं को स्थापित करते हुए भारत को कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के बढ़ते प्रभाव के परिदृश्य में भारत-चीन संबंधों की विवेचना कीजिये। (200 शब्द)

"China is launching a challenging challenge to India by establishing itself as a free-trade and open market head of the world in the traditional role of America. In the scenario of China's growing influence in the global economy, Discuss India-China relations. (200 words)